औद्योगिक गलियारा परियोजना

1. भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं को विकसित कर रही है जिसका उद्देश्य भारत में भावी औद्योगिक शहरों को विकसित करना है जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश गंतव्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह रोजगार अवसरों तथा आर्थिक वृद्धि का सृजन करेगा, जिसके फलस्वरूप सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।

2. 11 औद्योगिक गलियारों की 32 परियोजनाओं को 2024-25 तक 04 चरणों में विकसित किया जा रहा है:

i. दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी);
ii. चेन्नई बेंगलूरू औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी);
iii. अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी);
iv. चरण 1 में विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी) सहित ईस्ट कोस्ट औद्योगिक गलियारा (ईसीआईसी);
v. बेगलूरू मुंबई औद्योगिक गलियारा (बीएमआईसी);
vi. कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार;
vii. हैदराबाद नागपुरऔद्योगिक गलियारा (एचएनआईसी);
viii. हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा (एचडब्ल्यूआईसी);
ix. हैदराबाद बेंगलूरु औद्योगिक गलियारा (एचबीआईसी);
x. ओडिशाइकोनोमिक गलियारा (ओईसी);
xi. दिल्ली नागपुरऔद्योगिक गलियारा (डीएनआईसी).

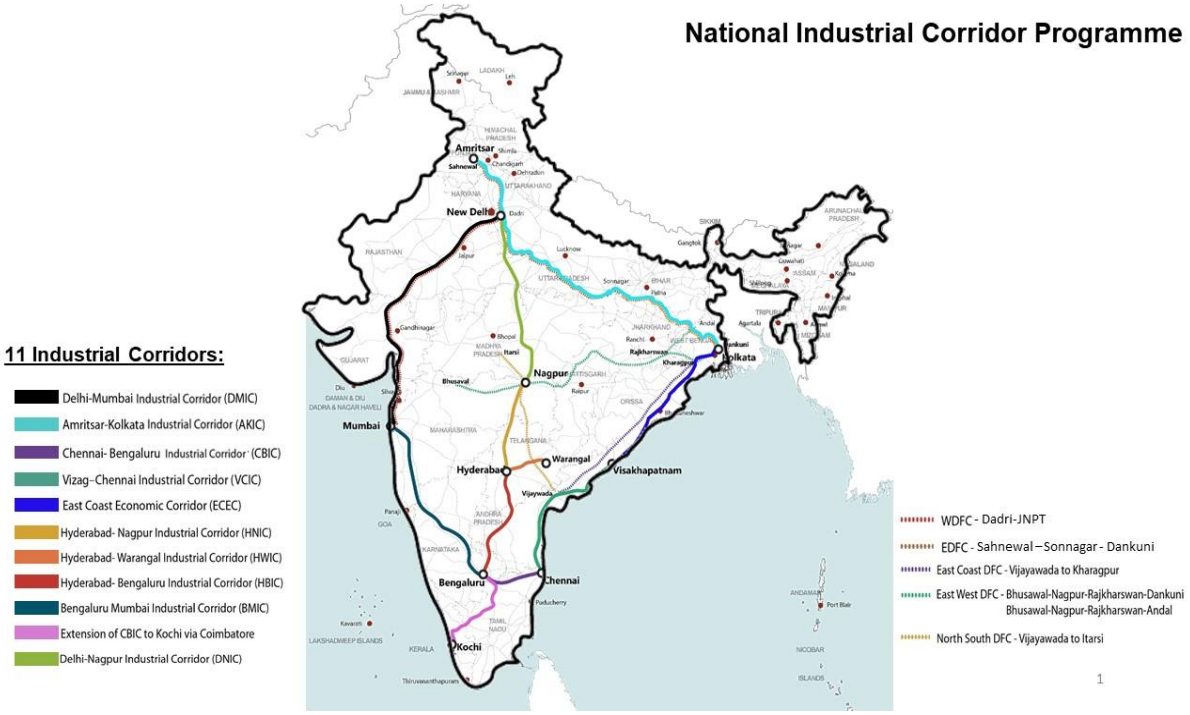

दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना विकसित करते समय, पश्चिमी डीएफसी को परिवहन आधार माना गया जबकि पूर्वी डीएफसी को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) परियोजना के लिए आधार माना गया है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी) और बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (बीएमआईसी) जैसी अन्य औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए एनएच-4 को मुख्य आधार माना गया है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (ईसीईसी) के लिए, एनएच-5 जो स्वर्णिम चतुर्भुज

का भाग है और कोलकाता-चेन्नई रेल मार्ग को परिवहन आधार माना गया है। प्रस्तावित उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम और पूर्वी तट समर्पित फ्रेट कॉरिडोर भी इन्हीं औद्योगिक गलियारों के लिए मौजूदा परिवहन आधार को पूरक करेंगे।

चरण 1: अनुमोदित परियोजनाएं

i. गुजरात में डीएमआईसी के अंतर्गत **धोलेरा स्पेशलइंवेस्टमेंट रीजन** (22.5 वर्ग किमी) http://dicdl.in/

ii. महाराष्ट्र में डीएमआईसी के अंतर्गत **शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया** (18.55 वर्ग किमी) https://www.auric.city/

iii. उत्तर प्रदेश में डीएमआईसी के अंतर्गत **इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा** (747.5 एकड़) https://www.iitgnl.com/

iv. मध्य प्रदेश में डीएमआईसी के अंतर्गत उज्जैन के समीप **इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप विक्रम उद्योगपुरी** (1100 एकड़) http://vikramudyogpuriujjain.com/

v. सीसीईए द्वारा डीएमआईसी के अंतर्गत हरियाणा में **नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब** (886 एकड़) अनुमोदित किया गया है और शीघ्र ही शुरु होने की आशा है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्यास्थी और संधारणीय भविष्य के तैयार शहरों के निर्माण के साथ-साथ भूखंड स्तर तक पूर्ण "प्लग एंड प्ले" बुनियादी ढांचे के साथ बहु-मॉडल संयोजकता प्रदान करना है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना के हिस्से के रूप में, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के 4 शहरों में पहले ही लागू की जा चुकी है और 536 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले 77 भूखंडों को अब तक लगभग 16,100 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ आवंटित किया गया है। कुल विकसित भूमि जो उद्योगों को आवंटन के लिए अतिरिक्त रूप से तैयार है, वह 3,620 एकड़ है और गैर-औद्योगिक उपयोगों के लिए 3,000 एकड़ है।

चरण 2: योजना और क्रियान्वयन के अग्रिम चरणों वाली परियोजनाएं जिन्हें 2021 तक शुरु किया जाना है

i. एनआईसीडीआईटी द्वारा आंध्र प्रदेश में **कृष्णापट्नम इंडस्ट्रियल एरिया** (2,500 एकड़) को अनुमोदित किया गया है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा जा रहा है

ii. सीबीआईसी के अंतर्गत कर्नाटक में **तुमकुरू इंडस्ट्रियल एरिया** (1736 एकड़) एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा जा रहा है

iii. डीएमआईसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)** (1208 एकड़) के लिए एनआईसीडीआईटी ने अनुमोदन दे दिया है और सीसीईए से अनुमोदन मांगा जा रहा है

iv. डीएमआईसी के भाग के रूप में, **दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया** (7,413 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी गतिविधियां पूरी हो गई है।

v. गुजरात में डीएमआईसी के अंतर्गत सानंद में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (500 एकड़) के लिए मास्टर प्लानिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है;

vi. हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के भाग के रूप में, **जहीराबाद** (3,500 एकड़) के लिए मास्टर प्लानिंग पूरी हो चुकी है

vii. हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर के भाग के रूप में, **हैदराबाद** (8,000 एकड़) के लिए मास्टर प्लानिंग पूरी हो चुकी है

viii. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर के भाग के रूप में **रघुनाथपुर** (2483 एकड़) के लिए मास्टर प्लानिंग पूरी हो चुकी है

चरण 3: विकास और क्रियान्वयनाधीन परियोजनाएं जिन्हें 2023 तक शुरु किया जाना है

i. सीबीआईसी के भाग के रूप में, **पोन्नेरी (4000 एकड़)** के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की गई है।

ii. सीबीआईसी के भाग के रूप में, केरल में **पालक्काड (1,878 एकड़)** के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी गतिविधियां शुरु हो गई है।

iii. सीबीआईसी के भाग के रूप में, **तमिलनाडु** में **धर्मपुरी सेलम (1,733 एकड़)** के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी गतिविधियां शुरु हो गई है।

iv. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर के भाग के रूप में, **हरियाणा** में **हिसार** (4000 एकड़) के लिए मास्टर प्लानिंग गतिविधियां शुरु की जा रही है।

v. आंध्र प्रदेश में कोपार्थी (4085 एकड़) के लिए वीसीआईसी कोरिडोर के लिए परियोजना विकसित करने संबंधी गतिविधियां शुरु की जा रही है।

vi. **आंध्र प्रदेश** के **चित्तूर** में (8967 एकड़) वीसीआईसी कोरिडोर के लिए परियोजना विकसित करने संबंधी गतिविधियां शुरु की जा रही है।

vii. **आंध्र प्रदेश** के **विजाग नोड** (4,311 एकड़) के लिए वीसीआईसी कोरिडोर के अंतर्गत, राज्य सरकार विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग करवा रही है।

viii. एकेआईसी कोरिडोर के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत **प्राग खुरपिया** (2,935 एकड़) में **इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर** शुरु किया जा रहा है और परामर्शदाताओं के लिए निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं।

ix. डीएमआईसी. कोरिडोर के अंतर्गत, राजस्थान में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है और परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शीघ्र ही शुरु की जाएंगी।

चरण 4: 2024 तक कार्यान्वयन आरंभ होने वाली संभावित परियोजनाएं

i. बीएमआईसी कोरिडोर के लिए, कर्नाटक में **धारवाड़** (5,800 एकड़) शुरु किया जा रहा है।

ii. बीएमआईसी कोरिडोर के लिए, महाराष्ट्र में **सांगली/सतारा/शोलापुर**नोड का प्रस्ताव है और राज्य सरकार को प्राथमिकता वाले नोड पर सहमति देने के लिए अनुरोध किया गया है।

iii. पंजाब में एकेआईसी के अंतर्गत **राजपुरा पटियाला** में इंटीग्रेटेड मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि की उपलब्धता के संबंध में पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शुरु हो गई है।

iv. उत्तर प्रदेश में एकेआईसी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए सरकार को प्राथमिकता वाले नोड पर सहमति देने के लिए अनुरोध किया गया है।

v. झारखंड में एकेआईसी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए सरकार को भूमि ब्यौरों की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया है।

vi. बिहार में एकेआईसी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मैन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए सरकार को भूमि ब्यौरों पर पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया है।

vii. ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर के लिए, दो नोड्स गोपालपुर, भुवनेश्वर कलिंगनगर (जीबीकेनोड) और पारादीप-केंद्रपाड़-धम्रा-सुबर्नरेखा (पीकेडीएसनोड) की पहचान की गई है और नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने के लिए हाल ही में एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया है और इन्हे आगे बढ़ाया जा रहा है

viii. हैदराबाद बेंगलूरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर के अंतर्गत ओर्वकल (आंध्र प्रदेश) नोड को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने के लिए हाल ही में एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया है और परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शुरु की जा रही है

ix. डीएमआईसी कॉरिडोर के अंतर्गत, राजस्थान में खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है और परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शीघ्र ही शुरु की जाएंगी।

x. दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शीघ्र ही शुरु की जाएंगी।

राज्य सरकार (रों) से परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शुरु करने हेतु प्रोजेक्ट एसपीवी को भूमि अंतरण करने अथवा व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए भूमि की पहचान करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।एनआईसीडीआईसी इन्हें फलीभूत करने हेतु राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में है।